

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	<p>पौष 14, सोमवार, शके 1942-जनवरी 04, 2021 <i>Pausa 14, Monday, Saka 1942-January 04, 2021</i></p>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-गुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसंबर 22, 2020

जी.एस.आर.238 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम 1988 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.-राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (2क) अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(2क) यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का फायदे लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा:

परंतु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में के किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा:

परंतु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा:

परंतु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तिक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार के अधीन पद से ऐसे पद अभिप्रेत हैं जो निम्न के अधीन हैं,-

- (क) राज्य सरकार के किसी विभाग या उससे संलग्न या अधीनस्थ कार्यालय;
- (ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई राज्य लोक उपक्रम उद्यम;
- (ग) संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय जिसका व्यय राज्य की संचित निधि से किया जाता हो ; या
- (घ) राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे जिस नाम से भी कहा जाये), या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन कोई निकाय ।”

3. नियम 6क का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 6क के विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

“(3) आवेदन के समय, कम्प्यूटर अर्हता सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, अनिवार्य नहीं होगी। नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने से पूर्व सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित कोई कम्प्यूटर अर्हता रखेगा। इसके अलावा कम्प्यूटर साक्षरता, सुसंगत सेवा नियमों में जहां कहीं भी विहित हो, से संबंधित शैक्षणिक अर्हताओं के अतिरिक्त, भारत सरकार की किसी रक्षा संस्था से न्यूनतम तीन माह का प्रमाणपत्र भी कम्प्यूटर अर्हता के रूप में स्वीकृत होगा।”

4. नियम 6ख का प्रतिस्थापन.-उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“**6ख. सेवानिवृत्ति के प्रमाण का प्रस्तुतिकरण.**- कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।”

5. नियम 18 क का संशोधन .-उक्त नियमों के नियम 18क में,-

(i). विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i). यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी विहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित, जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”;

(ii) खण्ड (ii) के विद्यमान उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(क) राज्य सेवाओं के लिए दस वर्ष:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा, ” ; और

(iii) खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ग) के नीचे उल्लिखित विद्यमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी; और ”

[सं.एफ. 5(18) डीओपी/ए-2/84 पार्ट 02]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह

संयुक्त शासन सचिव

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, December 22, 2020

G.S.R. .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 2.- After the existing sub-rule (2) and before the existing sub-rule (3) of rule 2 of the Rajasthan Civil Services (Absorption of Ex-servicemen) Rules, 1988, hereinafter referred to as the said rules, the following new sub-rule (2A) shall be inserted, namely:-

"(2A) Once an ex-serviceman has joined service on the post under the Government of Rajasthan after availing of the benefit of reservation, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government of Rajasthan would cease. After joining the employment under the Government of Rajasthan the person would be deemed to be a civil employee:

Provided that in case of direct recruitment where experience of a lower post is essential for any post the ex-serviceman shall not be debarred from the benefit of ex-serviceman category only because of being employed in government service on a lower post of which experience is required for the direct recruitment on the higher post.

Provided further that in case an ex-serviceman applies for various posts before joining any employment under the Government of Rajasthan and give self-declaration/ undertaking to concerned employer about the date-wise details of

application for various posts for which he/she had applied for before the joining the initial post under the Government of Rajasthan, shall not be debarred from the benefit of ex-servicemen category for appointment on such posts.

Provided also that the ex-serviceman who has been re-employed on Casual /Contract /temporary /ad-hoc basis under the Government of Rajasthan shall not be debarred from the benefit of ex-servicemen category."

Explanation : For the purpose of this rule post under the Government of Rajasthan means post under,-

- (a) any department of the State Government or its attached or subordinate office;
- (b) any State Public Sector Enterprise owned or controlled by the State Government;
- (c) any body established or constituted by the Constitution whose expenditure is met from the Consolidated Fund of the State; or
- (d) any body or board or corporation or authority or society or trust or autonomous body (by whatever name called) established or constituted by an Act of the State Legislature or a body owned or controlled by the State Government."

3. Amendment of rule 6A.- After the existing sub-rule (2) of rule 6A of the said rules, the following sub-rule (3) shall be added, namely:-

"(3) Computer qualification, wherever prescribed in the relevant service rules shall not be essential at the time of application. The appointee shall have to possess any of the computer qualification as prescribed in the relevant service rules before joining on the post. Moreover, in addition to the academic qualifications related to computer literacy, wherever prescribed in the relevant service rules, minimum three months certificate course from any defence institution of the Government of India shall also be accepted as computer qualification."

4. Substitution of rule 6B.- The existing rule 6B of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"6B. Submission of proof of Retirement.- A person who has retired after earning his or her pension or is retiring within forthcoming one year but has obtained no-objection certificate (NOC) from the competent authority, shall be eligible to apply for the post but shall have to submit proof of retirement to the appropriate Appointing Authority before joining. If an ex-serviceman applies on the basis on NOC and get selected before actual retirement, the appointing authority may relax the joining period and he shall be allowed to join the post within a period of two months of his retirement."

5. Amendment of rule 18A.- In rule 18A of the said rules,-

- (i) the existing clause (i) shall be substituted by the following, namely:-
 - "(i) if minimum marks in individual paper and/or in aggregate marks wherever prescribed to qualify the competitive examination for any post, relaxation of five percent or in case of non-availability of ex-serviceman, further more five percent or as prescribed in relevant service rules, whichever is higher shall be given to the ex-servicemen.";
- (ii) the existing sub-clause (a) of clause (ii) shall be substituted by the following, namely:-
 - "(a) for State Services - ten years:

Provided that in case of direct recruitment where experience is also essential on lower post then relaxation in age equal to the period of requisite experience of the lower post shall be given to the ex-servicemen in addition to the relaxation in age already provided under these rules,"; and

(iii) the existing proviso mentioned below to sub-clause (c) of clause (ii) shall be substituted by the following, namely:-

"Provided that permissible age after relaxation under this rule work out to be more than 50 years then upper age limit of 50 years shall be applicable but in case of direct recruitment where experience of lower post is essential the maximum upper age limit of 55 years shall be applicable; and"

[No. F. 5(18) DOP/A II/84 pt. II]

By order and in the name of the governor,

JAI SINGH

JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT

Government Central Press, Jaipur.